



दक्षिण भारत राष्ट्रमत

தக்ஷிண் பாரத் ராஷ்ட்ரமத் | தினகரி ஹிந்தி நாளிதழ் | चेन्नई और बेंगलूरु से एक साथ प्रकाशित



5 उपमुख्यमंत्री पद की मांग कर 'लालची' नहीं दिखना चाहता : चिराग पासवान

6 भारत में जलवायु संकट : स्वास्थ्य एवं समृद्धि पर कहर

7 'आज की रात' गाने पर रानी चटर्जी ने किया जबरदस्त डांस

फ़र्स्ट टेक

शिवकुमार ने जेल में बंद कांग्रेस के दो विधायकों से मुलाकात की

बेंगलूरु। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार ने बेंगलूरु सेंट्रल जेल परपन्नअग्रहारा का शुक्रवार को औचक दौरा किया तथा जेल में बंद कांग्रेस विधायकों विनय कुलकर्णी और के. सी. वीरेंद्र उर्फ पप्पी से मुलाकात की। प्राप्त जानकारी के अनुसार, शिवकुमार ने उनसे कुछ देर तक बातचीत की। कुलकर्णी हत्या के एक मामले में जेल में हैं, जबकि पप्पी धन शोधन के एक मामले में कैद हैं। कांग्रेस के एक सूत्र ने बताया, उन्हें (शिवकुमार) दो हफ्ते पहले उनसे मिलना था, लेकिन वह अब मिल रहे हैं। यह सिर्फ एक शिष्टाचार भेंट है और कुछ नहीं।

रुपया सर्वकालिक निचले स्तर 89.66 प्रति अमेरिकी डॉलर पर बंद

मुंबई/भाषा। अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले शुक्रवार को रुपया धराशायी हो गया जब डॉलर के मुकाबले यह 98 पैसे की जोरदार गिरावट के साथ 89 के स्तर को पार कर सर्वकालिक निचले स्तर 89.61 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। स्थानीय और वैश्विक शेयर बाजारों में बिकवाली के दबाव और व्यापार से जुड़ी अनिश्चितताओं के बीच घरेलू विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में डॉलर की जोरदार मांग के कारण रुपये में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। बाजार सूत्रों ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रौद्योगिकी शेयरों के आसपास हलचल को लेकर चिंताओं से भी निवेशकों की कारोबारी धारणा प्रभावित हुई। उन्होंने कहा कि इसके अलावा, विदेशी निधियों की ताजा धननिकासी से भी निराशा और बढ़ गई।

जापान ने 135 अरब डॉलर के प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दी

टोक्यो/एपी। जापान के मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को अर्थव्यवस्था को गति देने और उच्च किमतों के प्रभाव से राहत देने में मदद करने के लिए खर्च के माध्यम से 135.4 अरब डॉलर के प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दे दी। पिछले महीने पदभार संभालने के बाद प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने सरकारी खर्च बढ़ाने का वादा किया था। हालांकि ऐसी पहल को लेकर यह चिंता भी है कि इससे जापान का राष्ट्रीय ऋण कम करने की प्रक्रिया धीमी हो सकती है, जो उसकी अर्थव्यवस्था के आकार से लगभग तीन गुना है। यह खर्च पैकेज कोविड-19 महामारी से पहले के वर्षों की तुलना में कहीं अधिक है और इसका एक उद्देश्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जापानी निर्यात पर लगाए गए अधिक अमेरिकी शुल्कों के प्रभाव को कम करना भी है।

22-11-2025
सूर्योदय 5:39 बजे

23-11-2025
सूर्यास्त 6:11 बजे

BSE 85,231.92
(+400.76)

NSE 26,068.15
(+124.00)

सोना 12,878 रु.
(24 रुके) प्रति ग्राम

चांदी 175,000 रु.
प्रति किलो

मिशन मंडेला

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

दक्षिण भारत का लोकप्रिय हिन्दी दैनिक
epaper.dakshinbharat.com



केलाश मण्डेला, मो. 9828233434

सर्वारक्षण

हर जाति वर्ग में रहे सदा, कमजोर और पिछड़े अगड़े। युग-युग से ही होते आए, हकदारों के हक में झगड़े। आदोलन ना हो आए दिन, ना तोड़फोड़ के सब रगड़े, सबको ही दे दो आरक्षण, हो जाए खत्म सभी लफड़े।

एसआईआर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तृणमूल पर किया कटाक्ष

भारत से हर 'घुसपैटिये' को बाहर निकाला जाएगा : अमित शाह

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com



■ घुसपैट रोकना न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बल्कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को दृषित होने से बचाने के लिए भी आवश्यक है।

भुज (गुजरात)/भाषा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि सरकार देश से हर "घुसपैटिये" को बाहर निकाल देगी। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दल एसआईआर प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि घुसपैटियों के नाम मतदाता सूची में बने रहें। वह गुजरात के कच्छ जिले के भुज में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के हीरक जयंती (61वें स्थापना दिवस) समारोह को संबोधित कर रहे थे। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर शाह की टिप्पणी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार को कड़े शब्दों में पत्र लिखे जाने के एक

दिन बाद आई है, जिसमें उन्होंने (बनर्जी ने) इस प्रक्रिया को तुरंत रोकने का अनुरोध किया था। शाह ने कहा, "आज बीएसएफ देश की सभी सीमाओं पर घुसपैट रोकने में लगा हुआ है। घुसपैट रोकना न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बल्कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को दृषित होने से बचाने के लिए भी आवश्यक है।" एसआईआर को मतदाता सूची का शुद्धिकरण बताते हुए शाह ने कुछ राजनीतिक दलों पर अवैध घुसपैटियों के खिलाफ सरकार के अभियान को कमजोर

करने का प्रयास करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये पार्टियां निर्वाचन आयोग द्वारा जारी एसआईआर का विरोध कर रही हैं, क्योंकि वे यह सुनिश्चित करना चाहती हैं कि घुसपैटियों के नाम मतदाता सूची में बने रहें। शाह ने कहा, "मैं इस हीरक जयंती समारोह में बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम इस देश से एक-एक घुसपैटिये को चुन-चुन कर बाहर निकालेंगे। यह हमारा प्रण है। एक-एक घुसपैटिए को देश से बाहर निकालना मोदी सरकार का संकल्प है।" उन्होंने कहा, "देश के किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा या देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, यह निर्णय केवल भारत के नागरिक ही कर सकते हैं। घुसपैटियों को हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को दृषित करने और हमारे लोकतांत्रिक निर्णयों को प्रभावित करने का कोई अधिकार नहीं है।"

सरकार ने गिग वर्कर्स के लिए चार श्रम संहिताओं को अधिसूचित किया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। सरकार ने शुक्रवार को एक ऐतिहासिक फैसले में सभी चार श्रम संहिताओं को अधिसूचित कर दिया। इस प्रमुख सुधार के जरिये 29 मौजूदा श्रम कानूनों को तर्कसंगत बनाया गया है। इसमें गिग यानी अल्पकालिक अनुबंध पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा कवरेज, सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य नियुक्ति पत्र और सभी क्षेत्रों में वैधानिक न्यूनतम मजदूरी तथा समय पर भुगतान

■ सरकार ने 4 नई श्रम संहिताएँ लागू कर 29 पुराने कानूनों को आसान और एकसाथ कर दिया

■ अब हर श्रमिक को न्यूनतम वेतन, समय पर भुगतान, सामाजिक सुरक्षा और गिग वर्कर्स को भी लाभ मिलेगा

जैसे प्रावधान शामिल हैं। ये चार श्रम संहिताएँ – वेतन संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 तथा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशाएँ संहिता, 2020 हैं। सुधारों में महिलाओं के लिए विस्तारित अधिकार और सुरक्षा शामिल हैं। इनमें रात की पाली में काम, 40 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों के लिए मुफ्त वार्षिक स्वास्थ्य जांच, खतरनाक प्रक्रिया इकाइयों सहित पूरे भारत में ईएसआईसी कवरेज और एकल पंजीकरण, लाइसेंस प्रणाली शामिल हैं।

स्वतंत्रता के बाद से चार श्रम संहिताएं सबसे व्यापक, प्रगतिशील सुधार : मोदी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि सरकार द्वारा अधिसूचित चार श्रम संहिताएं आजादी के बाद से सबसे व्यापक और प्रगतिशील श्रम-उन्मुख सुधार हैं जो श्रमिकों को सशक्त बनाएंगी। मोदी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "इससे जहां नियमों का पालन करना बहुत आसान होगा, वहीं कारोबार में



सुगमता (ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस) को बढ़ावा मिलेगा।" ये चार श्रम संहिताएँ – वेतन संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 तथा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशाएँ संहिता, 2020 हैं। इनके जरिये 29

बका/भाषा। बांग्लादेश में शुक्रवार को आए 5.7 तीव्रता के भूकंप के कारण कम से कम छह लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। अधिकारियों के मुताबिक, भूकंप के झटके राजधानी ढाका और कुछ अन्य हिस्सों में महसूस किए गए तथा इस दौरान कई इमारतों को नुकसान पहुंचा और कुछ जगहों पर आग लग गई, जिससे निवासियों में हysteria फैल गई। अधिकारियों ने बताया कि ढाका में तीन लोगों, जबकि नारायणगंज में एक व्यक्ति की मौत की सूचना है। वहीं, दो अन्य मौतें नरसिंदाई में हुईं, जहां भूकंप का केंद्र सहित से लगभग 10 किलोमीटर नीचे स्थित था। स्थानीय मीडिया ने भूकंप के कारण देशभर में कम से कम 50 लोगों के घायल होने की खबर दी है।

भारत हजारों वर्षों से पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में मानता रहा है : योगी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com



'वसुधैव कुटुंबकम्' का उद्धोष करते हुए कहा कि 'भारत हजारों वर्षों से पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में मानता रहा है।' उत्तर प्रदेश की राजधानी में अतिथियों के आगमन पर राज्य

बढ़ाने और उसके संरक्षण में अपना योगदान न दिया हो।" योगी ने कहा, "आज हम दुनिया भर से जुड़े न्यायविदों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में यहां पर उपस्थित हुए हैं। इस अवसर पर सीएमएस लखनऊ के संस्थापक डॉक्टर जगदीश गांधी की स्मृतियों को नमन करता हूं, उन्हें विनम्र मद्दांजलि अर्पित करता हूं।" मुख्यमंत्री ने कहा, "उन्होंने ही वैश्विक एकता, शांति और न्याय के लिए प्रथम न्यायाधीशों के अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत की।"



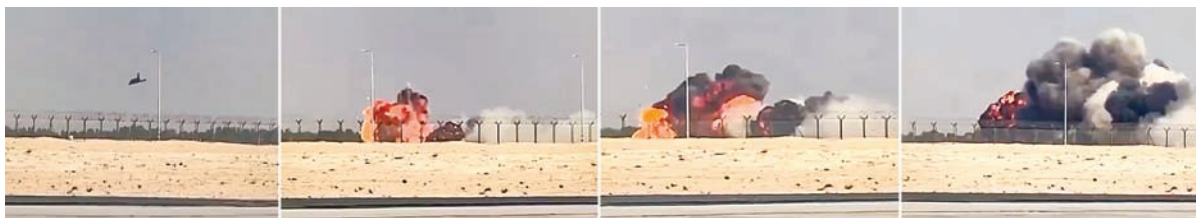
आज की नई दुनिया को नए संयुक्त राष्ट्र की आवश्यकता है : राजनाथ सिंह

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

लखनऊ/भाषा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कहा कि इजराइल-हमास और यूक्रेन-रूस जैसे वैश्विक संघर्षों और सूडान में जारी मानवीय संकट को हल करने में संयुक्त राष्ट्र काफी मजबूत भूमिका निभा सकता था। उन्होंने कहा कि आज की नई दुनिया को एक नए संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की आवश्यकता है। सिंह अपने संसदीय क्षेत्र

लखनऊ में सिटी मॉस्टरी स्कूल की ओर से आयोजित विश्व के प्रधान न्यायधीशों का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज दुनिया के विभिन्न हिस्सों में संघर्ष जारी हैं, जिनमें इजराइल-हमास संघर्ष, यूक्रेन-रूस युद्ध और सूडान समेत अफ्रीका के कई क्षेत्रों में जारी मानवीय संकट शामिल हैं। सिंह ने कहा, इन सब के बीच, हमें संयुक्त राष्ट्र से एक बहुत मजबूत भूमिका की उम्मीद थी। लेकिन हम ऐसा होता नहीं देख रहे हैं। ऐसा होता दिखना चाहिए था। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि

वैश्विक राजनीति की जटिलताओं, प्रमुख शक्तियों के प्रभाव और संस्थागत प्रक्रियाओं की धीमी गति के कारण ऐसा हो रहा है। उन्होंने कहा, इन कारकों ने अक्सर संयुक्त राष्ट्र की शक्तियों पर सवाल उठाए हैं। सिंह ने कहा, यह स्थिति तभी बरत सकती है जब हम संयुक्त राष्ट्र को पुनः उसके मूल उद्देश्य शांति, न्याय व समान प्रतिनिधित्व की ओर ले जाएं, जिसकी कल्पना इसकी स्थापना के समय की गई थी। उन्होंने कहा, मुझे दृढ़ विश्वास है कि आज की नई दुनिया को एक नए संयुक्त राष्ट्र की आवश्यकता है।



दुबई एयरशो में तेजस दुर्घटनाग्रस्त, पायलट की मौत

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/दुबई/भाषा। भारतीय वायुसेना (आईएफए) का लड़ाकू विमान तेजस शुक्रवार को दुबई एयरशो के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इस हादसे में पायलट

की मौत हो गई। आईएफए ने यह जानकारी दी। विभिन्न टीवी चैनलों पर दिखाए गए दुर्घटना के दृश्यों में विमान को ऊंचाई से गिरते और फिर आग के गोले में तब्दील होते देखा जा सकता है। वायुसेना ने एक संक्षिप्त बयान में कहा कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए एक 'कोर्ट ऑफ़

इन्क्वायरी' का गठन किया जा रहा है। मार्च 2024 में, वायुसेना का एक तेजस हल्का लड़ाकू विमान (एलसीए) पोखरण रेगिस्तान में सैन्य अभ्यास 'भारत शक्ति' से लौटते समय जैसलमेर में एक आवासीय कॉलोनी के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। यह ऐसी पहली दुर्घटना थी जो स्वदेश

निर्मित एकल इंजन वाले विमान के 2001 में उड़ान भरना शुरू करने के बाद हुई थी। उस समय में पायलट विमान से सुरक्षित रूप से बाहर निकल गया था। शुक्रवार को स्थानीय समयानुसार दोपहर में, एयरशो में हवाई प्रदर्शन के दौरान उड़ान भरते समय विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

ट्रंप की शांति योजना में यूक्रेन का कुछ हिस्सा रूस को देने का प्रस्ताव

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

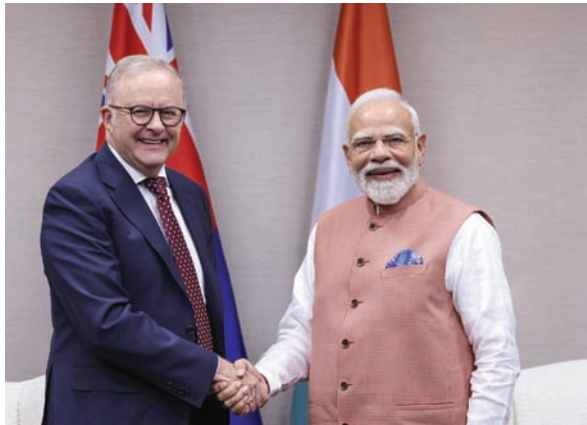


वार्शिंगटन/एपी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यूक्रेन युद्ध समाप्त करने की योजना के तहत यूरोपीय देश का कुछ हिस्सा रूस को सौंपने और उसकी सेना का आकार कम करने का प्रस्ताव शामिल किया गया है। यह जानकारी शांति के लिए तैयार मसौदे में दी गई है। अमेरिका और रूस के बीच हुई बातचीत के आधार पर यह मसौदा तैयार किया गया है, जिसकी एक प्रति 'एसोसिएटेड प्रेस' को बृहस्पतिवार को प्राप्त हुई। यह मसौदा साफ तौर पर रूस के पक्ष में दिखाई देता है। अमेरिकी प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न उजागर करने की शर्त पर बताया कि अमेरिकी टीम ने अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकोफ की यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के शीर्ष सलाहकार रुस्तम उमरोव से बातचीत के तुरंत बाद यह

योजना तैयार करना शुरू कर दिया था। अधिकारी ने बताया कि कई संशोधन करने के बाद उमरोव ने योजना के अधिकतर बिंदुओं पर सहमति जताई और फिर इसे जेलेंस्की के समक्ष प्रस्तुत किया। अधिकारी के अनुसार, अमेरिकी सैन्य सचिव डैन ड्रिस्कॉल भी बृहस्पतिवार को यूक्रेन की राजधानी कीव में थे और उन्होंने जेलेंस्की के साथ ताजा मसौदे पर चर्चा की। जेलेंस्की ने इस बारे में सोशल मीडिया पर एक संतुलित बयान दिया, लेकिन प्रस्ताव पर सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा। उन्होंने लिखा, यूक्रेन और अमेरिका की हमारी टीमें

शांति योजना के प्रावधानों पर मिलकर काम करेंगी। हम ईमानदारी, तेजी से और सकारात्मक माहौल में काम करने के लिए तैयार हैं। शांति योजना के तहत रूस को यह वादा करना होगा कि वह भविष्य में कोई हमला नहीं करेगा। इसके अलावा, रूस की 100 अरब डॉलर की जुमा संपत्ति को यूक्रेन के पुनर्निर्माण में इस्तेमाल किया जाएगा। इस पहल के तहत रूस को यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र 'ज़पोरिज़िया' से उत्पादित आधी बिजली का उपयोग करने की भी अनुमति होगी। इस संयंत्र पर रूस ने युद्ध की शुरुआत में ही कब्जा कर लिया था। हालांकि, पिछला रुख देखते हुए यह माना जा रहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर सकते हैं, क्योंकि वह पहले भी जमीन छोड़ने के ट्रंप के सुझावों का विरोध कर चुके हैं और यूक्रेन के संविधान के तहत ऐसी रियायत देना अवैध है।

मुलाकात



प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को यहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से मुलाकात की तथा दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय और आपसी हितों के मुद्दों पर चर्चा की। जी-20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए दक्षिण अफ्रीका पहुंचने के कुछ घंटों बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अल्बनीज से मुलाकात की। अल्बनीज ने दिल्ली में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले और सऊदी अरब में हुए बस हादसे पर दुख जताया।

छात्रा आत्महत्या: पीड़िता ने अपने आखिरी समय में पांच बार शिक्षक से मदद मांगी थी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नयी दिल्ली/जयपुर। सीबीएसई की एक जांच रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि जयपुर के एक स्कूल आत्महत्या करने वाली चौथी कक्षा की छात्रा को उसकी कक्षा में 18 महीने से ज्यादा समय तक परेशान किया गया तथा सहपाठी उसके खिलाफ बुरे शब्द इस्तेमाल करते थे जबकि स्कूल अच्छा माहौल बनाए रखने में नाकाम रहा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बोर्ड ने इस महीने की शुरुआत में स्कूल की



अपनी जिंदगी के आखिरी 45 मिनट में पांच बार शिक्षक के पास मदद मांगने गई। कक्षा चार की बच्ची ने एक

समिति ने अगले दिन स्कूल का मुआयना किया था और बच्ची के अभिभावकों से बातचीत की थी। बोर्ड ने कारण बताओ नोटिस में कहा, समिति को दिए गए माता-पिता के बयानों के मुताबिक, यह साफ है कि स्कूल ने सहपाठियों द्वारा परेशान किए जाने और धिंदाए जाने की बार-बार की शिकायतों पर कोई सक्रिय कार्रवाई नहीं की। कक्षा अध्यापक और स्कूल प्रबंधन को बच्ची को प्रताड़ित किए जाने के बारे में अच्छी तरह पता था।

बयान में माना है कि मृतक छात्रा ने उन्हें बताया था कि उसके सहपाठी उसके लिए बुरे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दूसरे छात्रों ने आरोपों से इनकार किया। हालांकि, दूसरे बच्चों ने पहले भी शिक्षक से कक्षा में छात्रों के बीच लगातार बुरे शब्दों के इस्तेमाल की शिकायत की थी। जयपुर के मानसरोवर इलाके में स्थित नीरजा मोदी स्कूल जयपुर के प्रतिष्ठित स्कूलों में से एक है। मानसरोवर थाने की पुलिस मामले की जांच कर रही है। थानाधिकारी लखन खटाना ने शुक्रवार को कहा कि मामले की जांच जारी है। उन्होंने कहा, पुलिस इस घटना के आपराधिक पक्ष की जांच कर रही है। अभी अनुसंधान जारी है।



उद्योगपति की बेटी की शादी के लिए उदयपुर में जुटेगी दुनियाभर की कई प्रमुख हस्तियां

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

उदयपुर। राजस्थान के उदयपुर में अमेरिका के दिग्गज उद्योगपति राजू रामलिंगा मंटोना की बेटी नेत्रा मंटोना की शादी होने वाली है जिसमें दुनियाभर की प्रमुख हस्तियों के शामिल होने की उम्मीद है। सूत्रों के अनुसार शादी में हॉलीवुड और बॉलीवुड की हस्तियों के अलावा राजनीति तथा उद्योग जगत के दिग्गज भी शामिल होंगे। इस शादी की तैयारियों से जुड़े व स्थानीय लोगों से प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय मूल के वामसी गड्डिआ और नेत्रा मंटोना ने अपने विवाह समारोह के लिए 'डीलिंग' के शहर उदयपुर को चुना है। विवाह समारोह के कार्यक्रम 21 नवंबर से 24 नवंबर तक चलेंगे। ये कार्यक्रम विख्यात उदयपुर सिटी पैलेस के माणक चौक तथा जनाना महल के साथ-साथ जगमंदिर और द लीला पैलेस होटल में होंगे।

अफ्रीका के डीजे-प्रोजेक्टर ब्लैक कॉफी भी अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। डीजे-प्रोजेक्टर टिएस्टो ने बुधवार रात 'द लीला पैलेस' में प्रस्तुति दी। पारंपरिक राजस्थानी नृत्य समूह और मांगणिया कलाकारों ने भी प्रस्तुति दी। इस शादी के लिए 'द लीला पैलेस' होटल को मेहमानों के स्वागत के लिए शानदार लाल 'थीम' पर सजाया गया है। मेहराबों से पुष्प गुच्छ लटके हुए हैं और इसे शाही दरबार जैसा रूप देने के लिए बड़े-बड़े झूमर लगाए गए हैं। बैठने की जगह पर खूबसूरत 'कुशन' और सुनहरे लैंप वाले लाल सोफे हैं। दूसरी जगहों को भी शानदार ढंग से सजाया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार 600 मेहमानों में ऋतिक रोशन, शाहिद कपूर और रणबीर कपूर समेत कई बॉलीवुड हस्तियां भी शामिल हैं।

नेत्रा मंटोना अमेरिका के दवा क्षेत्र के दिग्गज उद्योगपति राजू रामलिंगा मंटोना और पद्मा मंटोना की बेटी हैं। वह वामसी गड्डिआरू के साथ परिणय सूत्र में बंधेंगी जो मूल रूप से दक्षिण भारत के हैं और कई वर्षों से अमेरिका में बसे हुए हैं। विवाह समारोह में कई बड़ी हस्तियों के शामिल होने के मद्देनजर शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। शहर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। सिटी पैलेस के जनाना महल में 21 नवंबर को 'म्यूजिक नाइट' होगी। हल्दी की रस्म 22 नवंबर को होगी और इसके बाद 23 नवंबर की सुबह जगमंदिर में विवाह समारोह होगा और उसी शाम प्रीतिभोज होगा।

सहकारी समितियों को बनाया जा रहा आर्थिक रूप से सुदृढ़ प्रतिस्पर्धी : दक

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने कहा कि सहकारी समितियां बाजार की मांग के अनुरूप व्यावसायिक गतिविधियां आरम्भ कर आर्थिक रूप से सुदृढ़ एवं प्रतिस्पर्धी बनें, इसके लिए सरकार द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 के अंतर्गत सहकारिता विभाग द्वारा विभिन्न नवाचारों और गतिविधियों के माध्यम से सहकारी समितियों को आर्थिक सशक्त बनाया जा रहा है। इसी क्रम में जयपुर के वैशाली नगर में शुरू किया गया 'जना-उपहार सुपर मार्केट' एक महत्वपूर्ण गतिविधि है।

दक ने शुक्रवार को जयपुर के वैशाली नगर में राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ (कॉनफेड) एवं भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ (एनसीसीएफ) द्वारा ज्वाइंट वेंचर के अंतर्गत शुरू किये गए 'जना-उपहार सुपर मार्केट' का उद्घाटन किया। उन्होंने सुपर मार्केट का अवलोकन कर उत्पादों की जानकारी दी।

दक ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर की सहकारी संस्था सहकारी संस्थाओं के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

राजस्थान में हेवी रेयर अर्थ एलिमेंट के भण्डार

जयपुर। ब्रिटिश डिप्टी हाईकमीशन के प्रतिनिधियों ने मिनरल एक्सप्लोरेशन के कार्य में राजस्थान में कार्य करने में रुचि दिखाई है। प्रमुख सचिव माइस टी. रविकान्त से शुक्रवार को सचिवालय में ब्रिटिश डिप्टी हाईकमीशन के गुजरात-राजस्थान के डिप्टी हाईकमीशर स्टिफेन हिकलिंग, वरिष्ठ सलाहकार अहमदाबाद श्रीमती मोमिता भट्टाचार्य, वरिष्ठ ट्रेड सलाहकार अनुप नारायण और श्रीमती ब्रह्मदाया माया ने मुलाकात कर राजस्थान की खनिज संपदा और संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की। ब्रिटिश डिप्टी हाईकमीशन के चारों सदस्यों ने खासतौर से राजस्थान में क्रिटिकल और स्ट्रेटिजिक मिनरल्स के खोज खनन पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि डिप्टी हाईकमीशन इस समय गुजरात और ओडिशा में वहां की उपक्रमों के कोलोब्रेशन में काम कर रहा है। राजस्थान में खनन क्षेत्र में विपुल संभावनाओं को देखते हुए ब्रिटिश डिप्टी कमीशन राजस्थान में भी कोलोब्रेशन के साथ काम करने की संभावना तलाश रहा है। प्रमुख सचिव माइस टी. रविकान्त ने कहा कि राजस्थान में विविध प्रकार के खनिजों के विपुल भण्डार हैं। राजस्थान के सिवाना रिंग क्षेत्र में हेवी रेयर अर्थ एलिमेंट के डिपोजिट मिले हैं तो ग्रेनाइट, यूरेनियम, पोटाश आदि आदि क्रिटिकल मिनरल उपलब्ध हैं।

एसआईआर मतदाता सूची जांच निष्पक्ष चुनावों की दिशा में बड़ा कदम : सतीश पुनिया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जोधपुर। चुनाव सुधारों पर बोलते हुए उन्होंने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कहा कि एसआईआर मतदाता सूची का गहन परीक्षण लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपक्रम है। उन्होंने कहा कि टी.एन. सेशन के समय से चुनाव आयोग ने कई सुधार किए, लेकिन मतदाता सूची में डुप्लीकेसी और फर्जी नाम हमेशा से बड़ी चुनौती रहे हैं। पुनिया ने बताया कि सीमावर्ती क्षेत्रों से अवैध घुसपैठियों द्वारा पहचान पत्र बनाकर मतदान प्रक्रिया को प्रभावित करने की घटनाएँ सामने आती रही हैं। देश के भीतर भी कई स्थानों पर एक व्यक्ति के दोहरे, तीनतीन नाम दर्ज पाए गए, जिससे चुनाव की पारदर्शिता समाज के घेरे में रही। पुनिया ने स्पष्ट किया कि एसआईआर प्रक्रिया किसी राजनीतिक दल या समुदाय के खिलाफ नहीं, बल्कि चुनाव सुधार का निष्पक्ष चरण है। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में 60 लाख फर्जी मतदाता चिन्हित किए गए। अब ऑर्गेनिक मतदाता सूची के तहत प्रत्येक नागरिक का नाम केवल एक ही जगह रहेगा, जिससे फर्जी मतदान पूरी तरह रुकेगा। विपक्ष की आलोचनाओं पर पुनिया ने कहा कि राहुल गांधी और विरोधी दल इस प्रक्रिया से इसलिए असहज हैं क्योंकि इससे



फर्जी वोटिंग समाप्त होगी और वही वास्तविक नागरिक मतदान कर पाएगा। वोट चोरी पर पकड़े गए प्रश्न का उत्तर देते हुए पुनिया ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तंज करते हुए कहा कि कांग्रेस से बड़ा चोर कोई नहीं। जमीन से लेकर आसमान तक भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस पर लगे हैं। पुनिया ने कहा कि बिहार चुनाव में जनता ने वोट के जरिए कांग्रेस को जवाब दिया। राहुल गांधी को सलाह देते हुए उन्होंने कहा कि पुनिया ने सवाल के उत्तर दे दिए। आरोपप्रत्यारोप छोड़कर जमीनी राजनीति पर ध्यान दें। उन्होंने कहा कि राजस्थान में भी कांग्रेस का फर्जी मुद्दों पर आधारित आरोप किसी भी स्तर पर जनता का समर्थन नहीं पा पाएगा। सरस्वती नदी पर वैज्ञानिक आधार पर कार्य की जरूरतपूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने सरस्वती धरोहर संरक्षण मंत्री से उनकी विस्तृत चर्चा हुई है। पुनिया ने कहा कि वे यह जानने के विवाह समारोह में शामिल होंगे। शाम को वे सांचौर के लिए प्रस्थान कर गए।

हरियाणा और राजस्थानदोनों के किसानों को लाभ मिल सके। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिनमें जिला देहात अध्यक्ष विभूषन सिंह भारती, रंजीत कड़वासरा, पुखराज गोड, अयूब पठान, धनाराम थोरी, प्रताप सिंह भेड़, युवा जिला देहात उपाध्यक्ष पृथ्वी खोखर पूर्व जोधपुर जिला अध्यक्ष देहात जगराम बिशोई सहित अन्य कार्यकर्ता शामिल थे।

पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया का जोधपुर दौरा, एयरपोर्ट पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत जोधपुर। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया अपने एक दिवसीय दौरे पर जोधपुर पहुंचे, बताया जा रहा है। पुनिया विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। एयरपोर्ट पर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने साफा पहनाकर और मालाएं और पुष्प गुच्छ देकर जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रमों के अनुसार, पुनिया एयरपोर्ट से सीधे भाजपा कार्यकर्ता दिनेश चौधरी के निवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने उनके परिवार में मातृ शोक पर संवेदना व्यक्त करेंगे। इसके बाद वे सक्रित हाउस पहुंचेंगे और फिर अशोक बाहेरी के यहां आयोजित पारिवारिक शोक सभा में सम्मिलित होंगे। पुनिया ने जयंत सखला की पुत्री के विवाह समारोह में भी भाग लेंगे। इसके बाद वे संदीप काबरा की बेटी के विवाह समारोह में शामिल होंगे। शाम को वे सांचौर के लिए प्रस्थान कर गए।



मत्स्य राज्य मंत्री ने मत्स्य विभाग के नवीन ई- ऑक्शन पोर्टल एवं आईईसी सामग्री का किया लोकार्पण

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। मत्स्य एवं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेदम ने विश्व मत्स्य दिवस के अवसर पर शुक्रवार को सचिवालय में मत्स्य विभाग द्वारा एन.ई.एम.एल. के माध्यम से विकसित कराये गये नवीन ई- ऑक्शन पोर्टल एवं लाईसेंस मैनेजमेंट सिस्टम तथा विभाग द्वारा तैयार कराई गई प्रचार सामग्री का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि अब मत्स्य विभाग के काम की ऑनलाइन किए जायेंगे। इसके लिए विभाग के अधिकारी बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया। बेदम ने कहा कि अब ई-ऑक्शन पोर्टल के माध्यम से मत्स्य ठेके की बोली लगाने, ठेका राशि जमा कराने, अनुज्ञापत्र जारी करने इत्यादि कार्य विभाग की देख रेख में ऑनलाइन संपादित होंगे। शुरुआत में विभाग के ठेके से शेष "क" एवं "ख" श्रेणी के जलाशयों

के ठेके की कार्यवाही ई-ऑक्शन पोर्टल के माध्यम से की जायेगी। आगामी वर्ष से विभाग के "ग" एवं "घ" श्रेणी जलाशयों के मत्स्य ठेके की कार्यवाही भी इसी पोर्टल के माध्यम से संपादित किए जाने की योजना है। इस अवसर पर शासन सचिव मत्स्य एवं पशुपालन विभाग डॉ. समित शर्मा ने कहा कि इस पोर्टल के माध्यम से सम्पूर्ण ठेका प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शिता एवं निर्धारित समयानुसार की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त ठेका प्रक्रिया में लगने वाले समय की भी बचत होगी। उन्होंने विभाग कि वर्ष 2025-26 में ठेके से शेष रहे "क" एवं "ख" श्रेणी जलाशयों का श्रेणीवार एवं जिलेवार विवरण, इनकी आरक्षित दरे एवं निविदा संबंधी दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड किये जा चुके हैं। ठेका प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व इच्छुक बोलीदाताओं का पोर्टल पर पंजीकरण किया जा रहा है।

इस अवसर पर बेदम ने विभाग द्वारा संचालित भारत सरकार की प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना,

प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना के पैम्फलेट, पोस्टर, बुकलेट इत्यादि का भी लोकार्पण किया। इन सभी प्रचार सामग्री का विवरण राज्य के समस्त विभागीय कार्यालयों को किया जायेगा जिससे आमजन इन योजनाओं की जानकारी लेकर लाभान्वित हो सकेंगे। प्रचार सामग्री में खारे पानी में झींगा पालन, केज कल्चर, आर.ए.एस. एवं बायोफ्लोक तकनीक की जानकारी एवं मत्स्य पालन से संबंधित सामान्य ज्ञान बुकलेट भी तैयार कराई गई हैं। लोकार्पण कार्यक्रम में मत्स्य विभाग की निदेशक सविता बिशोई, विशिष्ट सचिव, डी.सी. मीणा, विभाग के संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, वरिष्ठ लेखाधिकारी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। कार्यक्रम के अन्त में बेदम ने उपस्थित समस्त विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विश्व मत्स्य दिवस की शुभकामनाएं देते हुए विभाग की उत्तरोत्तर वृद्धि की कामना की।

बीकानेर में आयोजित होगी पहली 'वेदांता दूर डी थार' अंतर्राष्ट्रीय साइकिल रैली

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की पहल पर बीकानेर में पहली बार 100 और 200 किमी लंबी 'वेदांता दूर डी थार' अंतर्राष्ट्रीय साइकिल रैली का आयोजन 23 नवम्बर को प्रातः 6.30 बजे से होगा। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शुक्रवार को सांकेट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इससे जुड़ी जानकारी दी। मेघवाल ने बताया कि वर्तमान समय में फ्रांस में 'दूर डी थार' के साइकिलिंग का अंतर्राष्ट्रीय इवेंट होता है। इसी तर्ज पर बीकानेर में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर की साइकिल रैली 'वेदांता दूर डी थार' का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यह आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'सांसद खेल महोत्सव-2025' के निर्देशानुसार युवा मामले और खेल मंत्रालय के फिट इंडिया के सहयोग व साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के तकनीकी सहयोग से किया जा रहा है। केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि इसकी शुरुआत

प्रातः 8.15 बजे भारतमाला एक्सप्रेस वे पर यह होगी। यह नौगंडेसर से देसलसर तक 50 किलोमीटर की दूरी में आयोजित की जाएगी। रैली के दौरान भारतमाला की एक साइड की 50 किमी की दूरी को पूरी तरह से ट्रैफिक फ्री रखा जाएगा। मेघवाल ने बताया कि ग्लोबल हैप्पीनेस फाउंडेशन की ओर से प्रायोजित इस साइकिल रैली में भारत के विभिन्न राज्यों के साथ साथ फ्रांस व जर्मनी के साइक्लिस्ट हिस्सा लेंगे। यह पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन नक्शे पर बीकानेर को नई रूपचान दिलाएगी। इससे फिट इंडिया का संदेश जाएगा। साइकिलिंग की भी प्रोत्साहन मिलेगा।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि रैली में फ्रांस, स्विट्जरलैंड और सिंगापुर समेत देश के विभिन्न राष्ट्रीय के 750 से अधिक साइकिल धावक भागीदारी निभाएंगे। इसमें बीकानेर जिले के भी लगभग 250 साइक्लिस्ट शामिल हैं। उन्होंने बताया कि पंजीकरण ऑनलाइन माध्यम से किया गया। हिस्सा लेने वालों में 662 पुरुष और 124 महिलाएं हैं। जिनमें 16 वर्ष से लेकर 69 वर्ष आयु तक के प्रतिभागी शामिल हैं। मेघवाल ने बताया यह साइकिल रैली 100 और 200 किलोमीटर

की श्रेणियों में होगी। दोनों ही रैली में आयु वर्ग और ओपन कैटेगरी रखी गई है। आयु वर्ग में पुरुष और महिला दोनों के लिए 16-30 वर्ष, 31-45 वर्ष और 45 वर्ष से ज्यादा तीन श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। वहीं ओपन कैटेगरी में किसी भी उम्र का कोई भी धावक हिस्सा ले सकेगा। प्रत्येक कैटेगरी में प्रथम तीन को पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। मेघवाल ने बताया कि प्रोफेशनल एलिट वर्ग में टॉप 10 प्रतिभागियों को महिला एवं पुरुष वर्ग में पुरस्कृत किया जाएगा। मेघवाल ने बताया कि रैली में कुल 27 लाख रूपए के पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रोफेशनल इलीट वर्ग में टॉप 10 पुरस्कार में क्रमशः सवा लाख, 90 हजार, 75 हजार, 60 हजार, 50 हजार, 40 हजार, 35 हजार, 30 हजार, 20 हजार, 15 हजार के पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। मेघवाल ने बताया कि 100 किलोमीटर टॉप ओपेन्चोर ग्रुप पुरस्कारों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहने वालों को क्रमशः 70 हजार, 55 हजार और 45 हजार का पुरस्कार व विभिन्न आयुवर्गों में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर रहने वाले प्रतिभागियों को क्रमशः 40 हजार, 30 हजार और 25 हजार के पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।

उत्कृष्टता की ओर राजस्थान पुलिस का रोडमैप बनेगा राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन

जयपुर। राजस्थान पुलिस अकादमी में शुक्रवार का दिन पुलिसिंग की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण रहा। शुक्रवार को पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा के निर्देशन में 'उत्कृष्टता के साथ पुलिसिंग-आगे की राह' विषय पर राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन का आयोजन किया गया। आज इस सम्मेलन से ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड पर राजस्थान के 600 पुलिस अधिकारी जुड़े और आधुनिक चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरे दिन तकनीकी नवाचारों, सामाजिक



सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर मंथन किया। राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन 2025 के उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि अनिल पालीवाल महानिदेशक पुलिस, प्रशिक्षण एवं यातायात रहे। सत्र के प्रारम्भ में महानिदेशक/महानिरीक्षक पुलिस,

सम्मेलन की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि व उसके मुख्य मुद्दों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। तत्पश्चात संजीव कुमार नाजरी, निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी द्वारा सम्मेलन का परिचय व अतिथियों का स्वागत कर उद्बोधित किया। गोविन्द गुप्ता, महानिदेशक

पुलिस एससीबी ने अपने उद्बोधन में कहा कि पुलिस के प्रत्येक व्यक्ति को बदलते परिप्रेक्ष्य के अनुसार दक्ष होने की आवश्यकता है और पुलिस नवाचारों हेतु सदैव कार्य करे व कुशलता बढ़ाये। आज पुलिस में डाटा बेस कम्प्यूटेशन की सख्त आवश्यकता है।

सुविचार

हर किसी को आजादी है, अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने का, पर आजादी में अपने कर्म को मत भूलना, याद रखना एक गलत काम, आप की आजादी छीन सकता है...!!!

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

देववाणी है संस्कृत

तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने संस्कृत को 'एक मृत भाषा' बताकर इस महान भाषा के योगदान और सांस्कृतिक महत्त्व की उपेक्षा की है। संस्कृत के खिलाफ सदियों से षड्यंत्र हो रहे हैं। इसे एक खास वर्ग की भाषा बताकर दुष्प्रचार किया जा रहा है। विदेशी आक्रांताओं ने इसे दबाने और मिटाने के लिए खूब चालें चली थीं, लेकिन नाकाम रहे थे। आज भी कुछ लोग यह कहकर संस्कृत को कमतर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस भाषा की कोई उपयोगिता नहीं है। उन्हें लगता है कि वे ऐसा कहकर प्रगतिशील और बड़े बुद्धिजीवी कहलाएंगे! वे विदेशी भाषाओं का गुणगान करते नहीं थकते। जैसे ही संस्कृत का जिक्र होता है, उन्हें सारी बुराइयां इसी में नजर आने लगती हैं। संस्कृत के बारे में गलत बयान वे लोग देते हैं, जिन्हें इसका ज्ञान नहीं है। संस्कृत को देववाणी यूं ही नहीं कहा गया है। इस भाषा ने हमारी संस्कृति को आकार दिया है। जो लोग इसे 'मृत भाषा' कहते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि इसके दो शब्दों- 'वंदे मातरम्' ने हमारे देश के स्वतंत्रता आंदोलन में नई ऊर्जा भर दी थी। हजारों क्रांतिकारियों ने इस उद्घोष के साथ बलिदान दिया था। विदेशी आक्रांता जानते थे कि भारत को गुलाम बनाए रखने के लिए इसकी आत्मा पर प्रहार करना होगा, इसलिए उन्होंने संस्कृत पर खूब प्रहार किए थे। उन्होंने इस दुष्प्रचार को हवा दी थी कि इस भाषा में कोरा अंधविश्वास भरा पड़ा है! हिंदी, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम, बांग्ला, गुजराती, मराठी ... सभी भाषाएं अच्छी हैं। भारत की सभी भाषाएं सुंदर हैं। क्या किसी भी भाषा को महान बनाने के लिए दूसरी भाषा को छोटी या कम महत्वपूर्ण बनाने की जरूरत है?

संस्कृत की बुराई करने का मतलब है- सभी भाषाओं की बुराई करना। ध्यान रखें, संस्कृत को सभी भाषाओं की मां कहा जाता है। इसकी शब्द रचना, व्याकरण आदि को विदेशी विद्वानों ने सराहा है। दुनिया की अनेक भाषाओं में संस्कृत के शब्द मिलते हैं। उनके कई शब्दों पर संस्कृत का गहरा प्रभाव है। अगर उन भाषाओं से वे शब्द निकाल दिए जाएं तो पीछे क्या बचेगा? संस्कृत ने अन्य भाषाओं को जीवन दिया है। जो लोग यह कहते हैं कि 'संस्कृत सिर्फ विवाह-मंत्र पढ़वाने के काम आती है', उन्हें इसके साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। नाटक, आयुर्वेद, रसायन शास्त्र, संगीत शास्त्र, गणित, खगोल शास्त्र ... संस्कृत ने मानवता की कितनी सेवा की है! अब तो पाकिस्तान में लोग स्वीकार करने लगे हैं कि अगर उनके हुक्मरानों ने चाणक्य का 'अर्थशास्त्र' पढ़कर नीतियां बनाई होतीं तो देश खुशहाल होता। संस्कृत के पीछे इस देश के असंख्य लोगों का तपोबल है। जब यहां मंदिर तोड़े जा रहे थे, पुस्तकालय नष्ट किए जा रहे थे, शिलालेख ध्वस्त किए जा रहे थे, तब भी कई परिवार ऐसे थे, जिन्होंने भिक्षा मांगकर गुजारा किया, लेकिन संस्कृत को मिटने नहीं दिया। वे पीढ़ी-दर-पीढ़ी ग्रंथों को कंठस्थ करते रहे। संस्कृत का संगीत अद्भुत है। कई विदेशी कलाकार संस्कृत में संगीत की प्रस्तुतियां दे रहे हैं। एक ब्रिटिश महिला ने अपना पूरा जीवन ही संस्कृत एवं संगीत को समर्पित कर दिया है। वे संस्कृत के विभिन्न मंत्रों, गीतों, स्तुतियों की बहुत मधुर प्रस्तुति देती हैं। चिंता, अवसाद, बेचैनी, अनिद्रा जैसी समस्याओं से पीड़ित लोगों को उनकी वाणी सुनकर बहुत शांति मिलती है। आज अंग्रेजों की संतानें संस्कृत सीखकर गर्व महसूस कर रही हैं, जबकि कई हिन्दुस्तानियों की संतानें इसे कोस रही हैं। क्या कहेंगे इसे? दुर्भाग्य, अज्ञान या कुछ और? अपनी मातृभाषा पर गर्व करना अच्छी बात है, लेकिन इससे किसी को यह अधिकार नहीं मिल जाता कि वह अन्य भाषाओं को मृत घोषित करे। नेतागण सद्भाव पैदा करें, विवाद नहीं।

ट्वीटर टॉक

झीलों की नगरी उदयपुर में घूमर महोत्सव 2025 की रंगीन धुनों से नीले आसमान, शांत झीलों और रोशनी से जगमगाते घाटों के बीच महिलाओं की अदाएं, उनकी सहज ताल और परंपरा के प्रति उनके प्रेम ने हर दर्शक का दिल जीत लिया।

—दिया कुमारी

घूमर महोत्सव 2025 के एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज होने पर सभी राजस्थानवासियों को हार्दिक बधाई! हमारी सरकार विकास के साथ-साथ विरासत को भी संजोने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

—भजनलाल शर्मा

हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सत्य, संघर्ष, धर्म, आस्था और तप की धरती ब्रह्म सरोवर पर अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित सनातन संस्कृति एवं 48 कोस कुरुक्षेत्र भूमि के तीर्थों की प्रदर्शनी का दर्शन करने का सोभाग्य मिला।

—सतीश पूनिया

प्रेरक प्रसंग

संस्कारों की ताकत

एक बार हाईस्कूल का एक छात्र अपने विद्यालय भ्रमण के दौरान उन स्थलों से रुबरु हुआ, जहां प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी शहीद हुए थे। भावुक और गद्गद छात्र अपने शिक्षक से चर्चा करके, शहीदों की वीरगाथाएं सुनकर और आसपास लगे कुछ पौधों की जानकारी प्राप्त करके शहीद स्थल के चबूतरे की सीढ़ियां उतरता है। फिर अपना जूता पहन लेता है। सामने पार्क की पतली सड़क पर पड़ी सीमेंट की बेंच पर वह बैठ जाता है और फिर से प्रतिमा को देखता है। इस बीच, वह देखता है कि तीन-चार लोग शहीद स्थल की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, उनमें से एक हैटधारी व्यक्ति हाथ में कैमरा पकड़े हुए है, और कुछ लोग सिगार पी रहे हैं। जूते-चप्पल पहने हुए ये लोग प्रतिमा के बिल्कुल पास जाकर खड़े हो जाते हैं। छात्र उनके पास जाता है और कहता है, 'आपको नंगे पैर आना चाहिए था, यह सही नहीं है। पवित्रता के दृष्टिकोण से ही, ऐसे स्थलों पर जूते-चप्पलें पीछे छोड़नी चाहिए।' यह बालक आगे जाकर एक प्रसिद्ध कैमरामैन बना और कुछ समय बाद महान फिल्मकार सत्यजीत रे के नाम से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुआ।

महत्त्वपूर्ण

Published by Bhupendra Kumar on behalf of New Media Company, Arihant Plaza, 2nd Floor, 84-85, Wall Tax Road, Chennai-600 003 and printed by R. Kannan Adityan at Deviyin Kanmani Achagam, 246, Anna Salai, Thousand Lights, Chennai-600 006. Editor : Bhupendra Kumar (Responsible for selection of news under PRB Act.) Group Editor - Shreekant Parashar. Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any such manner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.Regn No.RNI No. : TNHIN / 2013 / 52520

पाठकों से अनुरोध है कि प्रकाशन में प्रकाशित किए जाने वाले किसी भी तरह के विज्ञापन (वैवाहिक, र्ग्यक्रि, टेंडर एवं सजावटी इत्यादि) पर कोई भी कार्यवाही, प्रतिबद्धता या धनराशि का व्यय करने से पूर्व इन विज्ञापनों के बारे में समस्त जानकारी यह स्वयं प्राप्त कर लें। दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह उत्पादों की गुणवत्ता तथा सेवाओं के लिए विज्ञापनदाताओं द्वारा किए जा रहे किसी प्रकार के दावों के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर विज्ञापनदाता विज्ञापन में किया जा रहा दावा पूरा नहीं करता है तो दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह के संपादक, मुद्रक एवं प्रकाशक या मालिकान को पाठक किसी भी रूप में उत्तरदाई नहीं बना सकता। - दक्षिण भारत राष्ट्रमत

सामयिक

भारत में जलवायु संकट : स्वास्थ्य एवं समृद्धि पर कहर

ललित गर्ग

मोबाइल : 9811051133

जलवायु परिवर्तन से उपजी पर्यावरणीय चुनौतियाँ आज मानव सभ्यता के अस्तित्व तक को प्रभावित कर रही हैं। जलवायु परिवर्तन अब कोई दूर का वैज्ञानिक विचार नहीं, बल्कि तत्काल अनुभव किया जाने वाला यथार्थ है, जिसकी भयावहता का प्रमाण सीएसई और डाउन टू अर्थ की क्लाइमेट इंडिया 2025 की रिपोर्ट में स्पष्ट दिखाई देता है। जनवरी से सितंबर 2025 तक भारत ने अपने 99 प्रतिशत दिनों में किसी न किसी चरम मौसमी घटना-बाढ़, सूखा, भारी बारिश, तूफान, ठंड-लहर, अथवा भीषण गर्मी का सामना किया। इसी अवधि में 4,064 लोगों की मौत, 9.4% मिलियन हेक्टेयर फसल का नष्ट होना, लगभग 58,982 जानवरों की मृत्यु और 99,533 घरों का ढहना इस संकट की गहराई को दर्शाते हैं। कृषि क्षेत्र इन घटनाओं का सबसे बड़ा शिकार बना, क्योंकि जलवायु असंतुलन ने खेतों, मौसम चक्र और पैदावार को सीधे प्रभावित किया। बढ़ते तापमान और असामान्य वर्षा ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंचाई है। दुनिया के सबसे बड़ी आबादी वाले देश के सामने ये मुश्किलें सबसे बड़ी हैं। हिमाचल प्रदेश में 25% दिनों का चरम मौसम, मध्य प्रदेश में 532 मौतें और महाराष्ट्र में 84 लाख हेक्टेयर फसल का नुकसान बताता है कि यह सिर्फ पर्यावरणीय विषय नहीं, बल्कि मानव जीवन, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था का संकट है।

2025 में, कम से कम 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 2022 के बाद से सबसे अधिक चरम मौसमी दिन दर्ज किए गए। फरवरी से सितंबर 2025 तक, लगातार आठ महीनों तक देश के 30 या उससे अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चरम मौसम की घटनाएं रिकॉर्ड की गईं। भारत में जैसे हालात हैं, वही स्थिति पूरे विश्व में भी फैलती जा रही है। वर्ष 2023, 2024 और 2025 दुनिया के सबसे गर्म वर्षों में शामिल रहे। यूरोप की निरंतर हीटवेव, अफ्रीका के साहेल क्षेत्र का अकाल,

अमेज़न और ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग, प्रशांत और अटलांटिक महासागरों में उग्र तूफान, और ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने की घटनाएँ यह संकेत दे रही हैं कि पृथ्वी एक खतरनाक मोड़ की ओर बढ़ रही है। मौसम चक्रों का असंतुलन, समुद्र स्तर में वृद्धि, तापमान का अचानक बढ़ना और वर्षा का अनियमित होना, प्राकृतिक आपदाओं को न सिर्फ अधिक सघन बना रहा है बल्कि मानव जीवन को असुरक्षित भी। जलवायु परिवर्तन की सबसे बड़ी वजह मनुष्य की अनियंत्रित गतिविधियाँ हैं-जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता, वनों की कटाई, प्रदूषण, अनियोजित शहरीकरण और अत्यधिक उपभोग ने वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों को खतरनाक स्तर तक बढ़ा दिया है, जिसका परिणाम है पृथ्वी का असामान्य रूप से गर्म होना।

इन परिस्थितियों का असर जीवन के हर क्षेत्र पर दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य पर प्रभाव बढ़ रहा है, हीटवेव के कारण मौतें बढ़ रही हैं, नए वायरस और प्रदूषण से उत्पन्न बीमारियों की आयुति बढ़ी है। जल संसाधन खतरे में हैं और कई क्षेत्रों में नदियाँ व भूजल तेजी से सूख रहे हैं। खाद्य संकट गहराता जा रहा है क्योंकि फसलें असफल हो रही हैं, जिससे अनाज और सब्जियों की कीमतें बढ़ रही हैं। प्राकृतिक आपदाओं से आर्थिक ढाँचा भी डगमगा रहा है, लाखों लोग विस्थापित हो रहे हैं और असमानता तेजी से बढ़ रही है। यदि दुनिया ने तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने का लक्ष्य पूरा नहीं किया, तो आने वाले तीन दशकों में हिमालयी नदियों का प्रवाह अनिश्चित हो जाएगा, तटीय शहर खतरे में पड़ेंगे और मानव जीवन मुश्किल होता चला जाएगा।

जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को दर्शाती एक ओर रिपोर्ट पिछले दिनों द लांसेट काउंटडाउन ऑन हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज 2025' के अनुसार पिछले साल जलवायु परिवर्तन के कारकों से कृषि क्षेत्र में 66 फीसदी और निर्माण क्षेत्र में बीस फीसदी का नुकसान हुआ। यह रिपोर्ट इशारा करती है कि अत्यधिक गर्मी के कारण श्रम क्षमता में कमी के कारण 194 अरब डॉलर की संभावित आय का नुकसान हुआ। उल्लेखनीय है कि यह रिपोर्ट विश्व के %1 शैक्षणिक संस्थानों और संयुक्त राष्ट्र की

एजेंसियों के 128 अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने तैयार की, जिसका कुशल नेतृत्व यूनिवर्सिटी कालेज लंदन ने किया। इस रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य के बीच संबंधों का अब तक सबसे व्यापक आकलन किया गया है। रिपोर्ट बताती है कि साल 2020 से 2024 के बीच भारत में औसतन हर साल दस हजार मौतें जंगल की आग से उत्पन्न पीएम 2.5 प्रदूषण से जुड़ी थीं। चिंता की बात यह है कि यह वृद्धि 2003 से 2012 की तुलना में 28 फीसदी अधिक है, जो हमारी गंभीर चिंता का विषय होना चाहिए।

विडंबना यह है कि द लांसेट' की रिपोर्ट में सामने आए गंभीर तथ्यों के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस संकट से मिलकर जुड़ने की ईमानदार कोशिश होती नजर नहीं आती। यह निर्वाचन तथ्य है कि दुनिया के विकसित देश अपनी जिम्मेदारी से लगातार बचने के प्रयास कर रहे हैं। खासकर हाल के वर्षों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जलवायु परिवर्तन को लेकर जो गैरजिम्मेदाराना रवैया अख्तियार किया है, उससे नहीं लगता कि वैश्विक स्तर पर इस संकट से निपटने की कोई गंभीर साझा पहल निकट भविष्य में सिरे चढ़ेगी। विकसित देश इस दिशा में मानक पेरिस समझौते की संस्तुतियों को नजरअंदाज करते नजर आते हैं। सीएसई और डाउन टू अर्थ की क्लाइमेट इंडिया और द लांसेट काउंटडाउन ऑन हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज 2025 रिपोर्टों में उजागर तथ्य हमारी आंख खोलने वाले व सचेतक हैं।

इन्हीं चिन्ताजनक रिपोर्टों पर सीएसई की महानिदेशक सुनिता नारायण ने कहा, देश को अब सिर्फ आपदाओं को गिनने की जरूरत नहीं है, बल्कि उस पैमाने को समझने की जरूरत है जिस पर जलवायु परिवर्तन हो रहा है। उन्होंने वैश्विक स्तर पर उत्सर्जन कटौती की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया, क्योंकि इतने बड़े पैमाने की आपदाओं के लिए कोई भी अनुकूलन संभव नहीं होगा। सीएसई के कार्यक्रम निदेशक रिचम पांडे ने मानसून के दौरान बढ़ते तापमान को चिंताजनक बताया, जो अनियमित और चरम मौसमी घटनाओं को ट्रिगर कर सकता है। डाउन टू अर्थ के प्रबंध संपादक रिचर्ड महापात्रा ने कहा कि यह रिपोर्ट एक आवश्यक चेतावनी है और बिना निर्णायक शमन प्रयासों के आज

की आपदाएं कल का नया सामान्य बन जाएंगी। ऐसे समय में सिर्फ सरकारों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर आम नागरिक को भी पर्यावरण संरक्षण का सहभागी बनना होगा। सबसे पहले जीवनशैली को प्रकृति के अनुकूल बनाना जरूरी है, ऊर्जा की बचत, जल का सीमित और विवेकपूर्ण उपयोग, प्लास्टिक का परित्याग, वृक्षारोपण, जैविक कचरे का पृथक्करण और पुनर्चक्रण जैसी छोटी गतिविधियाँ बड़े परिणाम ला सकती हैं। घरेलू स्तर पर सौर ऊर्जा, वर्षा जल संचयन, रसोई कचरे से खाद बनाना और अनावश्यक उपभोग कम करना पर्यावरण पर सकारात्मक असर डालते हैं। वाहन का कम उपयोग, सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता, पैदल चलने और साइकिल जैसे पर्यावरण-मित्र विकल्प अपनाना जलवायु परिवर्तन से लड़ने की दिशा में शक्तिशाली कदम हैं।

पर्यावरणीय संवेदनशीलता भी उतनी ही आवश्यक है जितनी तकनीकी कोशिशें। प्रकृति के प्रति सम्मान की भावना, संसाधनों का संयमित उपयोग, और भविष्य की पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखने की दृष्टि, जलवायु संकट के खिलाफ हमारी सामूहिक ताकत बन सकती है। यदि समाज में यह चेतना विकसित हो कि प्रकृति का संरक्षण ही जीवन और प्रगति का आधार है, तो परिवर्तन स्वतः शुरू हो जाता है। शिक्षा, जागरूकता और जनभागीरथी इस लड़ाई के सबसे महत्वपूर्ण हथियार हैं। स्कूलों और घरों में बच्चों को पर्यावरणीय मूल्यों का प्रशिक्षण देना भविष्य के लिए अत्यंत उपयोगी होगा। जलवायु संकट अपने आप नहीं थमेगा; इसे रोकने के लिए संकल्प, संयुक्त प्रयास और सतत विकास को जीवन की प्राथमिकता बनाना आवश्यक है। पृथ्वी हमारे पास केवल एक है और उसका कोई विकल्प नहीं। समय का यही संदेश है कि यदि हम प्रकृति की चेतावनियों को गंभीरता से नहीं लेंगे, तो आने वाला समय मानवता के लिए और भी कठिन हो जाएगा। लेकिन यदि हर मनुष्य अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाए, तो जलवायु परिवर्तन की दिशा को बदल जा सकता है और धरती को संतुलन, शांति और स्थायित्व प्रदान किया जा सकता है।

नजरिया

प्री वेडिंग फोटो शूट : यादों का खजाना या मर्यादा का हनन ?

आजकल देशभर में प्री-वेडिंग शूट का एक चलन बढ़ता ही जा रहा है। पिछले कुछ सालों में प्री वेडिंग शूट शादी की फोटो एल्बम बनाने से ज्यादा जरूरी बन चुके हैं। प्री वेडिंग देश में एक लक्जरी इंडस्ट्री के रूप में उभर रहा है जो अपने बजट के हिसाब से किसी पार्क, रमणिक स्थल या किसी खूबसूरत स्थान पर ये शूट किए जाने लगे हैं। इसके तहत भावी दूल्हा- दुल्हन अपने परिवारजनों की सहमति से शादी से पूर्व फोटो आगर के साथ देश के अलग-अलग स्थानों पर सैर सपाटा करते हैं, बड़े होटलों, हेरिटेज बिल्डिंगों, समुद्री बीच व अन्य ऐसी जगहों पर जहाँ सामान्यतः पति पत्नी शादी के बाद हीमनूत मनाते जाते हैं, जाकर अलग-अलग और कम से कम परिधानों में एक दूसरे की बाहों में ससिते हुए वीडियो शूट करवाते हैं। विवाह से पहले किया जाने वाला वह फोटो/वीडियो ग्राफी जिसमें होने वाले भावी वंपति अपने विवाह से पहले, एक प्रेमी जोड़ी की भांति फोटो और वीडियो शूट करवाते हैं। जिसे वे मुख्य शादी वाले दिन बड़ी स्क्रीन पर एक शॉर्ट फिल्म के रूप में पेश करते हैं और सोशल मीडिया पर भी बड़े ही उत्साह के साथ पोस्ट करते हैं। इसे ही वीडियो शूट की संज्ञा दी जा रही है।

हाथों में प्री वेडिंग को लेकर हमारे समाज में तरह तरह की बातें सुनने को मिल रही है। वह भी एक समय था जब विवाह के दौरान फोटो खिंचवाकर उसे एल्बम में संजो कर रखते थे। इस एल्बम का क्रेज कुछ दिनों तक रहता और बाद में कहीं रखकर इसे भुला दिया जाता। समय बदला और अब हम डिजिटल युग में प्रवेश कर चुके हैं। कुछ समय पहले तक हम एल्बम के साथ वीडियो बनाकर अपने पास रख लेते थे। इस वीडियो को यदा कदा देख लेते थे। मगर अब हमारा डिजिटलीकरण हो चुका है और इसी के साथ प्री वेडिंग के नाम से एक नई प्रथा शुरू हो गई है। अब जमाना सोशल मीडिया का है। युवा अपनी हर घटना को सोशल मीडिया पर परोसने लगा है तो प्री वेडिंग कैसे पीछे रहता। अब प्री वेडिंग भी सोशल मीडिया पर देखी जाने लगी है। प्री वेडिंग के वीडियो और फोटो देखकर सामान्य परिवारों में काफी हलचल देखने को मिल रही है। कुछ लोग इसे पसंद कर रहे हैं तो कुछ ना पसंद कर रहे हैं। यहाँ से इसके समर्थन और विरोध में आवाजें बुलंद होने लगी है। कुछ सामाजिक संगठन इसे देश की संस्कृति के खिलाफ बता कर विरोध जता रहे हैं।

बताया जाता है प्री-वेडिंग शूट एक पाश्चात्य संस्कृति है। जो पिछले कुछ दशक से भारत में भी

नजरिया

बिहार की नई सरकार के सामने विकास की नई चुनौतियाँ

महेन्द्र तिवारी

मोबाइल : 9989703240

बिहार के 2025 विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिला प्रचंड जनादेश सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं, बल्कि राज्य की सामाजिक-आर्थिक मनोवृत्ति में आए परिवर्तन का संकेत भी है। यह परिणाम बताता है कि जनता ने स्थिरता, विकास और सुशासन के वादे पर विश्वास जताया है। लेकिन सत्ता का यह व्यापक अवसर उतनी ही बड़ी जिम्मेदारियाँ लेकर आता है। बिहार आज ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहाँ उम्मीदों का पहाड़ ऊँचा है और चुनौतियों की घाटियाँ गहरी। विकास का नया अध्याय तभी संभव होगा जब सरकार वादों से आगे बढ़कर उन्हें जमीन पर उतारने की विश्वसनीय रणनीति बनाए।

बिहार एक ऐसा राज्य है जिसकी सांस्कृतिक संपदा और ऐतिहासिक धरोहरें अद्वितीय हैं, लेकिन विकास के सूचकांकों पर उसकी छलाँग अभी अधूरी है। युवाओं की बड़ी मात्रा रोजगार के लिए बाहर जाती है, उद्योगों का आधार कमजोर है, और सामाजिक सुरक्षा ढाँचा अभी भी कई हिस्सों में छिन्नपूर्ण है। फिर भी, इस चुनाव परिणाम ने एक संदेश दिया है कि जनता परिवर्तन चाहती है-ऐसा परिवर्तन जो दिखे, छुए, और उनके जीवन में

वारंवार सुधार लाए। सरकार के 25 संकल्प इसी परिवर्तन की दिशा में रखी गई एक महत्वाकांक्षी नींव हैं। परंतु संकल्प तभी सार्थक होंगे जब वे ठोस नीति, पारदर्शी प्रशासन और सशक्त क्रियान्वयन से जुड़े हों।

रोजगार का प्रश्न बिहार की राजनीति और सामाजिक चिंताओं का सबसे बड़ा केंद्र रहा है। यहाँ के युवाओं को अक्सर प्रवासी मजदूर की पहचान लेकर जीना पड़ा है। नई सरकार ने एक करोड़ रोजगार सृजन का दावा किया है, जो उत्साहजनक जरूर है, लेकिन यह वादा सिर्फ घोषणाओं से पूरा नहीं हो सकता। इसके लिए औद्योगिक निवेश, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और लॉजिस्टिक्स के सुधार की जरूरत होगी। बिहार जैसे राज्य में

निजी निवेश आकर्षित करना आसान नहीं, लेकिन संभव भी नहीं। यदि सरकार उद्योगों के लिए स्थिर नीति, बेहतर कानून-व्यवस्था, और सरस्ती भूमि-सुविधाएँ सुनिश्चित करे, तो राज्य में उद्योगों का विस्तार संभव है। कृषि-आधारित उद्योग, फूड प्रोसेसिंग, टेक्नोलॉजी व स्टार्टअप मॉडल जैसे क्षेत्रों में अपार संभावनाएँ मौजूद हैं।

स्वास्थ्य और शिक्षा किसी भी राज्य की प्रगति की आत्मा हैं। मुफ्त शिक्षा, मेडिकल कॉलेजों का विस्तार और आधुनिक स्वास्थ्य ढांचे की घोषणा स्वागतयोग्य है। बिहार में स्वास्थ्य सेवाएँ अभी भी सीमित और असमान रूप से वितरित हैं। यदि सरकार स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत करे, डॉक्टरों की संख्या बढ़ाए, और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में

नियेश करे, तो राज्य की बड़ी आबादी को राहत मिल सकती है। इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, डिजिटल सुविधाएँ और कौशल-आधारित पाठ्यक्रम भविष्य के रोजगार परिदृश्य को मजबूत करेंगे।

भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना बिहार के विकास का अनिवार्य तत्व है। ई-गवर्नेंस, डिजिटल मॉनिटरिंग और पारदर्शी प्रशासन से ही जनता का विश्वास बहाल हो सकता है। भ्रष्टाचार विरोधी संस्थानों को मजबूत करना और नौकरशाही में जवाबदेही सुनिश्चित करना इस दिशा में अहम होगा। सरकार यदि इस मोर्चे पर सफल होती है, तो उसके बाकी संकल्पों का प्रभाव भी सहज ही दिखाई देगा। जनादेश बड़ा है, इसलिए अपेक्षाएँ भी बड़ी हैं। चुनौती यह नहीं कि सरकार ने कितने वादे किए हैं; चुनौती यह है कि वह कितने वादों को समयबद्ध, पारदर्शी और जनहितकारी तरीके से पूरा कर पाती है। बिहार का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि अगले पाँच साल में नीतियाँ कितनी दृढ़दर्शिता, ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ लागू होती हैं। यदि सरकार इन चुनौतियों को अक्सर में बदलने की क्षमता दिखाती है, तो बिहार वाकई में विकास का नया अध्याय लिख सकता है- और एक बार फिर देश को दिखा सकता है कि परिवर्तन इच्छा से नहीं, संकल्प और क्रियान्वयन से आता है।

महत्त्वपूर्ण

Published by Bhupendra Kumar on behalf of New Media Company, Arihant Plaza, 2nd Floor, 84-85, Wall Tax Road, Chennai-600 003 and printed by R. Kannan Adityan at Deviyin Kanmani Achagam, 246, Anna Salai, Thousand Lights, Chennai-600 006. Editor : Bhupendra Kumar (Responsible for selection of news under PRB Act.) Group Editor - Shreekant Parashar. Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any such manner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.Regn No.RNI No. : TNHIN / 2013 / 52520

पाठकों से अनुरोध है कि प्रकाशन में प्रकाशित किए जाने वाले किसी भी तरह के विज्ञापन (वैवाहिक, र्ग्यक्रि, टेंडर एवं सजावटी इत्यादि) पर कोई भी कार्यवाही, प्रतिबद्धता या धनराशि का व्यय करने से पूर्व इन विज्ञापनों के बारे में समस्त जानकारी यह स्वयं प्राप्त कर लें। दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह उत्पादों की गुणवत्ता तथा सेवाओं के लिए विज्ञापनदाताओं द्वारा किए जा रहे किसी प्रकार के दावों के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर विज्ञापनदाता विज्ञापन में किया जा रहा दावा पूरा नहीं करता है तो दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह के संपादक, मुद्रक एवं प्रकाशक या मालिकान को पाठक किसी भी रूप में उत्तरदाई नहीं बना सकता। - दक्षिण भारत राष्ट्रमत

